**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-3187**

**दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ**

**आईईएस का कार्यान्वयन**

**3187. श्री अनिल फिरोजिया:**
**श्री राहुल सिंह लोधी:**
**श्री जुगल किशोर:**
**श्री नलिन सोरेन:**
**डॉ. संजय जायसवाल:**
**श्री सतीश कुमार गौतम:**
**श्री प्रवीण पटेल:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जम्मू और दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित पूरे देश में इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दुमका और जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या दुमका और जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित झारखंड तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में इंडिया एनर्जी स्टैक के प्रमाणन या प्रायोगिक कार्यान्वयन के लिए किसी विद्युत वितरण इकाई या वितरण कंपनी (डिस्कॉम) का चयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए चुनी गई इकाईयों का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है, इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं और झारखंड और दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में आईईएस के कार्यान्वयन के लिए चरण-वार क्या समय-सीमा और रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ) इंडिया एनर्जी स्टैक से विद्युत क्षेत्र में डिजिटलीकरण, अंतर-प्रचालनीयता और दक्षता में किस प्रकार सुधार होने की संभावना है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) से (ङ) :** इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) की परिकल्पना विद्युत क्षेत्र को डिजिटली सक्षम बनाने हेतु की गई है, ताकि विद्युत प्रणाली के अलग-अलग खंड मानक डेटा विनिमय प्रोटोकॉल के माध्यम से सुरक्षित रूप से आपस में जुड़ सकें तथा संचार कर सकें। विद्युत मंत्रालय ने घटक एवं डिज़ाइन सहित आईईएस हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए मंत्रालयों, राज्य यूटिलिटी, विनियामकों, जेनको

एवं ट्रांसको के प्रतिनिधियों सहित डोमेन विशेषज्ञों तथा विभिन्न हितधारकों का एक कार्यबल गठित किया है।

दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मुंबई की वितरण यूटिलिटी को आईईएस के पायलट (प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट) कार्यान्वयन हेतु चिह्नित किया गया है, तथा इसके प्रदर्शन की समय-सीमा वित्त वर्ष 2026-27 है। आईईएस का कार्यान्वयन वर्तमान में केवल पायलट कार्यान्वयन हेतु चयनित वितरण यूटिलिटी के संबंध में ही शुरू किया गया है।

आईईएस का उद्देश्य एक एकीकृत, सुरक्षित एवं अंतर-प्रचालनीय डेटा विनिमय तंत्र विकसित करना है, ताकि विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सेवाएं एवं प्रणालियां निर्बाध रूप से एक साथ कार्य कर सकें। आईईएस द्वारा तैयार सक्षम प्रणाली का उद्देश्य वितरण क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने से संबंधित प्रौद्योगिकी समाधानों तथा लोड पूर्वानुमान, मांग अनुक्रिया कार्यक्रमों, ऊर्जा लेन-देन एवं विद्युत क्षेत्र में समग्र डिजिटलीकरण जैसी उपभोक्ता-केंद्रित सेवाओं के निर्बाध एकीकरण को सुगम बनाना है।

**********